अध्ययन किए जाते हैं। बाल श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का आकलन करने के उद्देश्य से 1991 की जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण अभी आना है।

**Complaints against Purolator India Ltd.**

3342. SHRI N. GIRIPRASAD : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of complain's/cases are lying in the various labour courts regarding harassment of employees by the management of M/s. Purolator India Limited, New Delhi;

(b) if so, what are the details thereof and the action Government propose to take against the said company to remedy the situation;

(c) whether it is also a fact that the management of the Co. through pressure asks its staff to resign on flimsy grounds to avoid non-payment of terminal benefits to them; and

(d) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (d) According to the information furnished by the Government of National Capital Territory of Delhi, 21 Industrial Disputes between the management of M/s Purolator India Ltd. and its workmen are pending in various Industrial Tribunals/Labour Courts in Delhi. The matter being subjudice, any further action can be initiated only after the decision of the Industrial Tribunals/Labour Courts.

**विक्रय प्रोन्नति कर्मचारियों का शोषण**

3343. **श्री कामेश्वर पासवान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विक्रय प्रोन्नति कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम 1976 की उपधारा 2घ (1) और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(घ) में उचित तालमेल न होने के कारण औषध एवं उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में कार्यरत पर्यवेक्षकों का शोषण हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी और इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालक औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(घ) के अंतर्गत "कामगार" के रूप में परिभाषित हैं भले ही उनका वेतन कितना ही क्यों न हो, जबकि औषध एवं उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में कार्यरत पर्यवेक्षकों के लिए इस संबंध में 1600 रुपए के वेतन की सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार विक्रय प्रोन्नति कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम 1976 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में समुचित संशोधन करके पर्यवेक्षकों के लिए 1600 रुपए प्रतिमाह की निर्धारित सीमा को पूर्णतः समाप्त करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा)** : (क) विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 की धारा 2 (घ) के अंतर्गत "विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी" की परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (घ) के अंतर्गत "कर्मकार" की परिभाषा पर आधारित है और इसमें मुख्यतः प्रबंधन अथवा प्रशासकीय हैसियत के रूप में नियोजित व्यक्ति (ली गई मजदूरी को ध्यान में रखे बिना) तथा पर्यवेक्षी हैसियत पर नियोजित व्यक्ति और 1600/- रुपए प्रति माह से अधिक वेतन लेने वाले शामिल नहीं हैं। इस प्रकार, उपरोक्त दो अधिनियमों में वर्णित कर्मकार/कर्मचारियों और प्रबंधकों/पर्यवेक्षकों की परिभाषा में कोई विरोधाभास नहीं है।

(ख) जी हां, भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों और इंडियन एअर-लाइन्स के पायलटों को प्रबन्धकीय, प्रशासकीय अथवा पर्यवेक्षी हैसियत के रूप में नियोजित नहीं समझा जाता है और इस प्रकार उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत "कर्मकार" समझा जाता है। इस प्रकार के मामलों में वेतन की कोई सीमा नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**ESI Hospital at Sonagiri Madhya Pradesh**

3344. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the ESI hospital at Sonagiri in the State of Madhya Pradesh is miserably under-staffed and the number of trained doctors in various disciplines of specialised treatment is inadequate resulting in avoidable hardships to the industrial workers;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government propose to take to provide adequate and specialised doctors at the ESI hospital at Sonagiri ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (c) According to the Government of Madhya Pradesh, which is statutorily responsible for administration of ESI medical care in M.P., the ESI hospital at Sonagiri is not miserably under-staffed. Specialists' services are being provided in all the basic specialities. The services of specialists in the medical college hospital are also being utilised where necessary. However, the State Govt. has taken further initiatives to improve the working of the hospital.

**Incorrect information given by Purolator India Ltd.**

3345. SHRI N. GIRIPRASAD : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government are aware that M/s Purolater India Ltd. New Delhi has furnished incorrect/misleading information to the Employment Exchange at Pusa Road regarding the number of persons employed by them and those required by it;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether any inquiry has been conducted in this regard; if so, what are the details thereof; if not, what are the reasons therefor; and

(d) what action Government have taken or propose to take against the said company for supplying wrong information ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (d) According to the information furnished by the Government of the National Capital Territory of Delhi, some discrepancies were observed in the figures reported by M/s Purolater India Ltd., New Delhi and those actually obtaining as per their record.

It is for the Government of the National Capital Territory of Delhi, which is the appropriate authority, to take such necessary action as deemed fit.

**"चाइल्ड प्रोडक्शन स्कीम" के अंतर्गत धोखाधड़ी**

3346. **श्री राम नरेश यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "चाइल्ड प्रोडक्शन स्कीम" के अंतर्गत ईरान और इराक में रोजगार दिलाए जाने के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों में पिछले छह महीनों से आज तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और